SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन

विजय कुमार यादव, शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
विजय कुमार यादव,
शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 21/09/2020
Revised on : -----
Accepted on : 28/09/2020
Plagiarism : 04% on 22/09/2020

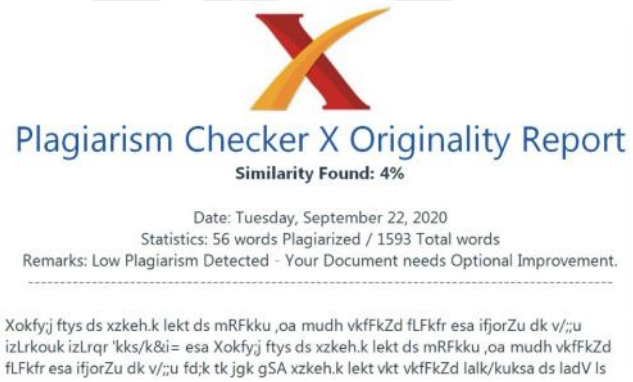

शोध सार

प्रस्तुत शोध–पत्र में ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा है। ग्रामीण समाज आज आर्थिक संसाधनों के संकट से जूझ रहा है जिसकी एक प्रमुख वजह ग्रामीणों में जागरूकता की कमी का होना है जिससे उनके उत्थान में बाधा आ जाती है। शासन–प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों का उत्थान हो सके। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द

ग्रामीण समाज, उत्थान एवं आर्थिक स्थिति।

भारत प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति ही नहीं बल्कि इसकी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास भी लगभग पांच हजार वर्ष पुराना माना गया है। दुनिया की प्राचीन पुस्तकों में से एक मनुस्मृति में भी इस प्राचीन युगीन ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में मनुष्य जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जंगली जीवन व्यतीत करता था। इस जीवन से मुक्ति पाने के उपरान्त विकासशील अवस्था में मनुष्य ने विविध आवश्यकताओं का अनुभव किया। मनुष्य जिज्ञासु तो प्रारंभ से ही था जिस समय तक वह कबीलियायी और घुमन्तु जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय राजनीतिक चेतना संभवत अचेतन अवस्था में रही होगी। किन्तु मनुष्य ने जैसे ही घुमन्तु शिकारी जीवन का परित्याग करके स्थायी ग्रामीण जीवन प्रारम्भ किया तो उसे शान्ति और विकास की आवश्यकता महसूस होने लगी और संभवतः इसी आवश्यकता ने उसे विकास के

प्रति उत्थान एवं आर्थिक स्थिति के परिवर्तन की समस्या को जन्म दिया।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण जन समुदाय पूर्णरूप से शिक्षित एवं सुसंस्कृत नहीं है। प्रशासन के क्षेत्रों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में हमारा अनुभव न्यून है। यहां तक कि अपने स्वयं के अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान भी लोगों को नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विशाल देश के प्रशासन और विकास की समस्या और भी जटिल बन जाती है। सरकार और जन प्रतिनिधि इस बात पर सहमत है हमारे यहां ग्रामीण विकास के चरम लक्ष्य तक पहुँच पाना एक कठिन कार्य है क्योंकि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि जन समुदाय को विकास के प्रति जागरूकता एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त न हो। इस दिशा में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में हुई प्रगति विकास का अवलोकन करने तथा राष्ट्र के सामने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक प्रयत्नों की ओर ध्यान देने का उचित समय आ गया है। सरकार द्वारा जारी अनेक योजनायें है, जिनका उद्देश्य अच्छा है लेकिन इन योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने के लिये योजनाओं के बारे में विस्तार से सोचने की और उनके सफल क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण समुदाय को इन योजनाओं की पूरी जानकारी भी नहीं होती है। अतः जिनके लिये योजनायें बनायी जाती है, उन्हीं को अगर योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया का अंग बना दिया जाये तो योजनाओं की सफलता की संम्भावनायें बढ़ सकती है। भारतीय शौचालय योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधि का आंवटन भी वास्तविक आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम होता है। सफल घरेलु उत्पाद में कृषि के लिये निवेश के प्रतिशत में हो रही लगातार गिरावट इसकी पुष्टि करती है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता भी चिंता का एक और क्षेत्र है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रशासन से सम्बन्धित अभी तक व्यवस्थित अध्ययन का अभाव रहा है। किसी कार्यक्रम विशेष पर अथवा संगठनात्मक, कार्यात्मक संरचना तक अध्ययन सीमित रहे है। कई अध्ययनों में केवल प्रशासनिक तन्त्र का समावेश किया है तो कहीं जनता का अथवा जन प्रतिनिधियों का आनुभाविक परन्तु इस अध्ययन में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिकता पर दृष्टिपात करने का प्रयास किये गये हैं और साथ ही अनुभाविक अध्ययन में ग्रामीण विकास तन्त्र के कार्मिक तन्त्र, जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता को सम्मिलित किया है।

वर्तमान में देश की राजनैतिक एवं आर्थिक अस्थिरता की इस विकट घड़ी में विकास सरकार के लिये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस परिप्रेक्ष्य में जन भागीदारी एवं जागरूकता का महत्व और भी बढ़ जाता हैं आज देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पुर्ननिर्माण का वातावरण बना हुआ है। इसमें पंचायतों एवं ग्रामीण जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित एवं महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में समाज के वंचित, कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिये ऐसे अध्ययनों की खासी आवश्यकता है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान कर ग्रामीण विकास की राह आसान की है। इससे कमजोर, पिछड़े लोगों को जहां नीति निर्माण, निर्णयन एवं क्रियान्वयन में सहभागिता का अवसर मिलेगा, वही जागरूकता एवं अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ेगी। यह अध्ययन पूर्व, अध्ययनों में अनछुए विविध पहलुओं की रिक्तता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

शोध के उद्देश्य

शोध अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं :

1. ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान का अध्ययन करना।
2. ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध विधि

आज के परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर जिले के ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन किया जाना औचित्यपूर्ण एवं आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है क्योंकि शोध समस्या के लिए यही विधि सर्वोत्तम है।

अध्ययन क्षेत्र एवं न्यादर्श

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के गाँवों में ग्रामीण समाज की सहभागिता एवं राजनीतिक जागरूकता का सर्वेक्षण ग्वालियर जिले के अंतर्गत चार तहसीलें – मुरार, डबरा, भितरवार एवं घाटीगांव की कुल 256 ग्राम पंचायतों के 561 ग्रामों में से चारों तहसीलों के प्रत्येक पाँच गाँवों में ग्रामीण समाज की सहभागिता एवं राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन करने हेतु कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

शोध परिसीमन

शोध मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के ग्रामों तक ही सीमित किया गया है।

शोध उपकरण

उत्तरदाताओं के लिए स्व–निर्मित साक्षात्कार अनुसूची शोधार्थी द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श उपरान्त तैयार की गई जिसे भरवाकर तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

स्व–निर्मित साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण प्रतिशत सांख्यिकी विधि द्वारा किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण

तालिका क्र.1 : ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी निम्नतम स्थिति पर प्रभाव के लिए जिम्मेदारी संबंधी तालिका

सं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
अ.	शासन को	140	46.67
ब.	समाज को	100	33.33
स.	स्वयं को	55	18.33
द.	कोई जवाब नहीं	5	1.67
	योग	**300**	**100.00**

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह तालिका 300 उत्तरदाताओं से यह पूछने पर ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी निम्नतम स्थिति पर प्रभाव के लिए आप जिम्मेदार मानते है को दर्शाती है इसमें शासन को जिम्मेदार मानने वाले की संख्या 140 (46.67 प्रतिशत), समाज को जिम्मेदार मानने वालों की संख्या 100 (33.33 प्रतिशत) हैं और स्वयं को जिम्मेदार मानने वाली की संख्या 55 (18.33 प्रतिशत) है, 5 (1.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जबाव नहीं दिया।

तालिका क्र. 2 : ग्रामीण विकास हेतु प्रयासों से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने सम्बन्धी तालिका

सं.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
अ.	हाँ	150	50
ब.	नहीं	150	50
	योग	**300**	**100**

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह तालिका 300 उत्तरदाताओं से यह पूछने पर आप मानते हैं कि ग्रामीण विकास हेतु प्रयासों से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुए हैं? या नहीं को दर्शाती है, इसमें हाँ में उत्तर देने वालों की संख्या 150 (50.00 प्रतिशत), नहीं में उत्तर देने वालों की संख्या 150 (50.00 प्रतिशत) है।

निष्कर्ष

अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण समाज के उत्थान एवं उनकी निम्नतम स्थिति पर प्रभाव के लिए शासन को

जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि शासन की योजनाएं ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए होती हैं परन्तु उनका लाभ ग्रामीण जनों को पूर्ण रूप से मिल पाता है क्या? यह सभी जानते हैं। भ्रष्टाचार के चलते शासन द्वारा लागू किसी भी योजना का पूर्ण लाभ ग्रामीण जन को नहीं मिल पाता है।

ग्रामीण विकास हेतु प्रयासों से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के संदर्भ में आधे उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति दर्शायी है व आधे ने असहमति। पंचायत राज, विशेषकर ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के लिए जितने भी प्रावधान हैं वे सभी इसी एकजुटता के माध्यम से सामाजिक पूंजी को बनाने और बढ़ाने की बात करते हैं। इसीलिए अगर हम यह कहें कि किसी भी समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास में ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस प्राथमिक आधार के अलावा जिस मूलभूत संरचना की आवश्यकता सामाजिक–आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में पड़ती है वह भी पंचायत है कि विकास के लिए आधार की ही नहीं वरन् सहायक तत्वों की भी व्यवस्था पंचायत के माध्यम से ही होती है।

सुझाव

1. ग्रामीण विकास के लिए उन्हें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। जहाँ–जहाँ गाँवों में विद्यालय नहीं है वहाँ पर विद्यालय का निर्माण कराया जाए। शिक्षा का व्यापक प्रसार कर शिक्षा को सुलभ बनाया जाए।
2. सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों को सतत् रोजगार तथा न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
3. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा।
4. ग्रामीणजनों के नेतृत्व के कार्य का विस्तार किया जाए और इसे सक्रिय राजनीति से जोड़कर इनके अधिकारों तथा कर्तव्यों का विस्तार किया जाए तथा इन्हें प्रत्येक स्तर को मजबूत बनाया जाये।
5. ग्रामीणजनों को विस्तारपूर्वक सरकारी नीतियों की जानकारी दी जाये जिससे वे लाभान्वित हो सकें।

संदर्भ सूची

1. *अग्रवाल, डॉ. अमित (2013), भारत में ग्रामीण समाज, विवेक प्रकाशन दिल्ली।*
2. *दुबे एस.सी. 'एक भारतीय ग्राम' नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।*
3. *यादव, सुबह सिंह, सत्य भवन (1997). ''ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन'', सब लाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर।*
4. *जाट सांवर लाल, शर्मा प्रकाश (1991), ग्रामीण विकास एक अध्ययन, (ग्रामीण विकास के बाधक पहलू) सब लाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर।*
5. *महाजन डॉ. संजीव, (2017), भारत में ग्रामीण समाज, अर्जुन पब्लिकेशन नई दिल्ली।*

****